an>

Title: Need to probe the alleged irregularities in the auction of cooprative sugar mills in Maharashtra.

श्री राजू शेट्टी (हातकणंगले) ः महाराष्ट्र के को-ऑपरेटिव चीनी उद्योग में राज्य सरकार, किसान, आम आदमी की बड़ी राशि निवेश है। महाराष्ट्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही चीनी उद्योग पर निर्भर है। लगभग 9 लाख गन्ना कटाई करने वाले मज़दूरों को साल में 150 से 170 दिन का रोज़गार यह उद्योग देता है। हज़ारों मज़दूर चीनी मिलों में काम करते हैं और 3 करोड़ गन्ना उत्पादक किसानों की आजीविका इस उद्योग पर निर्भर है। लेकिन पिछले कई सालों से यह उद्योग कथित रूप से भ्रष्टाचार, परिवारवाद और राजनीति का शिकार बन गया है। एक-एक पैसा इकट्ठा करके किसानों ने यह चीनी उद्योग अपने पसीने से खड़ा किया। लेकिन किसानों की धनराशि राजनीति के लिए इस्तेमाल की गई। नतीजा यह हुआ कि सहकारी चीनी मिलें घाटे मे चली गयी। आखिरकार उसका कर्ज इतना बढ़ गया कि बैंकों को सेक्युरिटाइजेशन एक्ट के तहत चीनी मिलों की नीलामी करनी पड़ी। मज़े की बात यह है कि जिनकी वजह से चीनी मिलों की नीलामी हुई, उन्हीं राजनीतिक नेताओं ने अलग-अलग अपनी निजी प्राइवेट कंपनियां बनाकर अलग-अलग नाम से नीलामी में उन्हीं मिलों की खरीदारी की। इस नीलामी में कहीं भी पारदर्शिता दिखाई नहीं दी। आज तकरीबन एक चीनी मिल खड़ा करने के लिए कम से कम 300 करोड़ रूपये लगते हैं। लेकिन यही सहकारी चीनी मिले केवल 14 करोड़ रूपये से 50 करोड़ रूपये तक में नीलाम हो गयी। पिछले कई सालों में महाराष्ट्र की 35 सहकारी चीनी मिले सिर्फ 1 हज़ार 76 करोड़ में नीलाम हो गयी, जिनकी असली बाज़ार कीमत 10 हज़ार करोड़ से भी ज्यादा है। मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि जिन निजी कंपनियों ने यह चीनी मिले खरीदी हैं, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन हैं, शेयर होल्डर कौन हैं और वह यह मिल खरीदने के लिए इतनी राशि कहां से लाए। इसकी पूर्वतन निदेशालय (ई.डी.) की तरफ से पूरी जांच की जानी चाहिए। इसके साथ-साथ सहकारिता की कई स्पीनिंग मिले, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट को भी इसी तरह से बेचा गया और खरीदारी हुई। इसमें जो राशि लगायी गयी है, वह सब कालाधन है।

सरकार से मेरा आग्रह है कि इस पूरे मामले की ई.डी. के तहत जांच करके असली हकदारों के साथ न्याय किया जाए।

12.58 hours

DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 2016-17